Statement-I

National agricultural extension project I Madhya Pradesh Financial assistance received during last three years.

Rs. in million

Project Effective/ closing date	State covered	Total cost of the project	Total expenditure	Credit disbursement ending March 1993 (including previous 3 yrs.)	Advance released to Madhya Pradesh	Central assistance (ACA)	
					1990-91	1991-92	92-93
National Agricultural Extension Project-I	Madhya Pradesh	145.60	150.10	132.861	..	10.0	4.0
Effective: 1994							
Closing; *March* 1993							

Statement-II

Physical targets and achievements under MAEP Madhya Pradesh

Project/State	Staff positioning		Civil work		Vehicle procurement		Trg. of the extn. persons	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8	9
National Agricultural Extension Project—Madhya Pradesh	14596	14507	470	448	2755	1967	9609	5207

Agricultural productivity in India and USA

7114. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) wether it is a fact that about seven million people in U.S.A. are engaged in agriclutture whereas in India there are about 5090 million people engaged in agriculture;

(b) whether it is also a fact that the production of foodgrains in these two countries is almost the same;

(c) if so the reasons thereof; and

(d) whether Government is consi dering a scheme to lessen the burden of people on land, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No. According to the F.A.O. Production Year Book, 1992, population engaged in agriculture in U.S.A. and India were 6 million and 546 million respectively.

(b) No. According to the same source, foodgrains production in U.S.A. and India in 1992 was of the order of 355 million tonnes and 212 million tonnes (with rice considered in terms of paddy) respectively.

(c) The difference is due to high level of mechanisation and producti vity in U.S.A.

(d) Diversification of agriculture and development of secondary and territory is expected to ease the pressure of population on land.

Centeral Assisince for Rehabillltation in Gujarj

7115. '-SHRIMATH BASANTI SH-ARMA: WILL the QAi9fflfTI ISH- Minister of AGRICULTURE be pleased *to* state:

(a) whether *the* Government of Assam has submitted a request for seeking Central Assistance for re-habilitatoin and to make up for the losses suffered due to floods in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount sanctioned for the purpose and the amount actually re leased so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

. (b) and (c) Do not arise.

पठार विकास परियोजना के अधीन योजनायें

7116. श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदम जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विश्व-बैंक द्वारा वित्त पोषित पठार विकास परियोजनाओं के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन और रख-रखाव का खर्च आदिवासियों से वसूल किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विशेषकर किन-किन परियोज-नाओं के संबंध में "लागत की वापसी" के सिद्धान्त को अपनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(घ) विश्व बैंक द्वारा अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से देश में चलाई जा रही कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं/योजनाओं की कुल संख्या कितनी हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि लगभग सभी योजनाएं अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है और क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

परियोजना में, बिहार सरकार तथा परियोजना के लाभानुभोगियों के बीच लागत और लाभ की हिस्सेदारी के लिए सहमत व्यवस्था के माध्यम से लागत की कुछ राशि की वसूली का प्रावधान हैं ।

(ख) लागत की वसूली के कारणों में निम्न बातें शामिल हैं :-

(1) लाभानुभोगियों को कार्यकलापों तथा उनके स्थानों के चयन सहित परियोजना आयोजन प्रक्रिया में शामिल करना, तथा (2) लाभानुभोगी इनमें से कुछ परिसम्पत्तियों के स्वामी हों और उनका उपयोग करें।

(ग) परियोजना लाभानुभोगियों के साथ लागत की हिस्सेदारी की व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में चलाने का प्रस्ताव है– (1) सिंचाई स्कीमें (2) जल संग्रहण टैंक/खुदे हुए कुएं, (3) पीने के पानी की सुविधाएं, (4) पनधारा उपचार आदि ।